

जनतंत्र की मूल भावना पर न हो आघात

विश्वनाथ सचदेव

दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गिरफतार होंगे, यह सब जाते थे। सवाल सिफ़ कब गिरफतार होंगे का था। अब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफतार कर लिया है। यह शब्द लिखे जाने वाले उन्हें जमानत नहीं मिली है। और इसी तरह की पहली गिरफतारियों को देखते हुए यहीं लग रहा है कि जमानत आसान नहीं है। ईडी सरकार के इशारों पर काम करती है, इस आशय के आरोप लगाने वाले यह भी कह रहे हैं कि आम-चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफतार करके केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के एक कदमवर नेता को चुप करने का काम किया है। पिछले एक अर्से से जिस तरह विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर बनाने की कोशिश हो रही है, उसे देखते हुए केजरीवाल को गिरफतारी पर न तो आशय व्यक्त किया जा सकता है, और न ही यह कहा जा सकता है कि यह गिरफतारी अप्रत्याशित थी। यह अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं है कि इस समय ही यह गिरफतारी क्यों हुई है चुनाव से ठीक पहले हुई इस गिरफतारी से मतदाता को एक संदेश तेज मिलता ही है कि गिरफतार होने वाले ने कुछ तो गुलत किया ही है। वहीं शायद केजरीवाल भी गिरफतारी का राजनीतिक लाभ उठाने की उम्मीद में बैठे थें हुए वह स्वयं को पीड़ित दिखाकर मतदाता की सहानुभूति की उम्मीद कर ही सकते हैं।

मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी को इस तरह गिरफतार किए जाने की भले ही यह पहली घटना हो, पर जारखंड के मुख्यमंत्री को भी लगभग इसी तरह कमज़ोर बनाया गया था। यह सही है कि गिरफतारी से ठीक पहले उन्होंने पद से त्यागपत्र देकर अपने उत्तराधिकारी की राह आसान बना दी थी, पर मामला यहीं तक सिंधित नहीं था। सवाल मुख्यमंत्री की इस तरह की गई गिरफतारी के राजनीतिक संकेतों का है। किसी के जरीवाल अथवा किसी सोरेन ने उसे कोई अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई के मंत्र्यों को समझने की भी आश्वासकता होती है। जिन स्थितियों में और एसी कार्रवाई हुई है, यह हो रही है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि इस सबके पांछे विपक्ष को कमज़ोर बनाने और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है। सरकार यह कह कर पहले नहीं झाड़ सकती कि ईडी, सीबीआई, इनकमटैक्स जैसी संस्थाओं को सांविधानिक संरक्षण प्राप्त है और उनके कामकाज में सरकार दखलांदाजी नहीं करती। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के ही एक माननीय न्यायाधीश ने कभी सीबीआई को 'पिंजरे में बंद तोता' कहा था। सत्ता की राजनीति में तब और आज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाए देता। देखा जहा जा रहा है कि जन-समर्थन राजनीतिक नेतृत्व को एकाधिकारी बना देता हुए बड़ा बना रहा है। जनतंत्रिक अथवा अन्य संसाधनों की बद्धता जननदर से अर्थात् और सामाजिक ताने बनाने पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वर्ष 2022 के संयुक्त राष्ट्र के अंकड़ों के मुताबिक पिछले दस वर्षों में एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले आठ देशों की आबादी कम हो गई है, जिनमें ज्यादातर देश यूरोपी के हैं। जापान आबादी में आ रही गिरावट व बुजुर्जों की बढ़ी आबादी से परेशान है। इसका सामाजिक अर्थात् आर्थिक हालात पर असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय जननदर द लेस्ट में 20 मार्च 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लड़कों की आबादी दर घटने के कारण सामाजिक ताने बनाने पर असर पड़ रहा है। जीवन शैली में बदलाव की बजह से युवा शादियां विलम्ब से करने लगे हैं, जिसका असर बच्चों के पालन-पोषण, उनकी शिक्षा और सेवा पर पड़ता है। इससे सामाजिक ताना-बाना गड़बड़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 तक यानी 74 साल पहले भारत की प्रजनन दर जो 6.2 थी, 2021 साल आते-आते घट कर दो प्रतिशत से भी कम रह गई। अध्ययन व अनुमान के मुताबिक 2050 तक प्रजनन दर घट कर 1.29 और साल 2100 में घटने-घटते 1.04 तक पहुंच सकती है। गौरतलब है जैपान ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए युवाओं को इनाम दे रहा है। इसके बावजूद शादी करने वाली संख्या लगातार कम हो रही है। यानी जैपान आबादी में आ रही गिरावट व बुजुर्जों की बढ़ी आबादी से परेशान है। इसका सामाजिक अर्थात् आर्थिक हालात पर असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय जननदर द लेस्ट में 20 मार्च 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लड़कों की आबादी दर घटने के कारण सामाजिक ताने बनाने पर असर पड़ रहा है। जीवन शैली में बदलाव की बजह से युवा शादियां विलम्ब से करने लगे हैं, जिसका असर बच्चों के पालन-पोषण, उनकी शिक्षा और सेवा पर पड़ता है। इससे सामाजिक ताना-बाना गड़बड़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 तक यानी 74 साल पहले भारत की प्रजनन दर जो 6.2 थी, 2021 साल आते-आते घट कर दो प्रतिशत से भी कम रह गई। अध्ययन व अनुमान के मुताबिक 2050 तक प्रजनन दर घट कर 1.29 और साल 2100 में घटने-घटते 1.04 तक पहुंच सकती है। गौरतलब है जैपान ज्यादा बच्चे पैदा होती है और इससे लड़कों का मतलब बढ़ते की आबादी में बढ़ती है। यानी ब्रह्म शक्ति में कमी आना। यह किसी भी देश के लिए एक जोखिम की स्थिति हो सकती है। भारत को भी एक या दो दशक ब्रह्म शक्ति की कमी से सम्प्रभावों का समान करना पड़ेगा।

विकसित देशों में भी जन्म-मृत्यु दर में असंतुलन पैदा हो गया है। अध्ययन के मुताबिक 2030 तक स्पैन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर और जर्मनी की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और न्यूग्यांग की आबादी की घटना भी थम सकती है। अभी हालत यह है कि कई विकसित देशों में बच्चों की बजह से परेशान है। अब ताकि आबादी की घटना नहीं हो जाएगी। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और न्यूग्यांग की आबादी की रस्तार भी थम सकती है। अभी हालत यह है कि कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान में बच्चों की जन्मदर 0.97 प्रतिशत है तो जन्मदर 0.6 है। कोरिया में प्रजनन दर 0.72 प्रतिशत है। इस तरह देखें तो जन्मदर उन देशों में सबसे कम है जो विकसित और अन्य संसाधनों के बाजी जाना चाहिए। इनमें आपीकी देशों के अलावा मध्यपूर्व के मुदिलम देश भी शामिल हैं। वहीं जिन देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत अधिक है, उन देशों में आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न के अलावा दवाएं व रोजगार की कमी आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न और रोजगार की कमी है। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और न्यूग्यांग की आबादी की रस्तार भी थम सकती है। अभी हालत यह है कि कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान में बच्चों की जन्मदर 0.97 प्रतिशत है तो जन्मदर 0.6 है। कोरिया में प्रजनन दर 0.72 प्रतिशत है। इस तरह देखें तो जन्मदर उन देशों में सबसे कम है जो विकसित और अन्य संसाधनों के बाजी जाना चाहिए। इनमें आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न के अलावा दवाएं व रोजगार की कमी आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न और रोजगार की कमी है। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और न्यूग्यांग की आबादी की रस्तार भी थम सकती है। अभी हालत यह है कि कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान में बच्चों की जन्मदर 0.97 प्रतिशत है तो जन्मदर 0.6 है। कोरिया में प्रजनन दर 0.72 प्रतिशत है। इस तरह देखें तो जन्मदर उन देशों में सबसे कम है जो विकसित और अन्य संसाधनों के बाजी जाना चाहिए। इनमें आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न के अलावा दवाएं व रोजगार की कमी आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न और रोजगार की कमी है। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और न्यूग्यांग की आबादी की रस्तार भी थम सकती है। अभी हालत यह है कि कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान में बच्चों की जन्मदर 0.97 प्रतिशत है तो जन्मदर 0.6 है। कोरिया में प्रजनन दर 0.72 प्रतिशत है। इस तरह देखें तो जन्मदर उन देशों में सबसे कम है जो विकसित और अन्य संसाधनों के बाजी जाना चाहिए। इनमें आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न के अलावा दवाएं व रोजगार की कमी आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न और रोजगार की कमी है। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और न्यूग्यांग की आबादी की रस्तार भी थम सकती है। अभी हालत यह है कि कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान में बच्चों की जन्मदर 0.97 प्रतिशत है तो जन्मदर 0.6 है। कोरिया में प्रजनन दर 0.72 प्रतिशत है। इस तरह देखें तो जन्मदर उन देशों में सबसे कम है जो विकसित और अन्य संसाधनों के बाजी जाना चाहिए। इनमें आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न के अलावा दवाएं व रोजगार की कमी आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न और रोजगार की कमी है। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और न्यूग्यांग की आबादी की रस्तार भी थम सकती है। अभी हालत यह है कि कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान में बच्चों की जन्मदर 0.97 प्रतिशत है तो जन्मदर 0.6 है। कोरिया में प्रजनन दर 0.72 प्रतिशत है। इस तरह देखें तो जन्मदर उन देशों में सबसे कम है जो विकसित और अन्य संसाधनों के बाजी जाना चाहिए। इनमें आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न के अलावा दवाएं व रोजगार की कमी आपीकी देशों के पानी, खाद्यान्न और रोजगार की कमी है। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और न्यूग्यांग की आबादी की रस्तार भी थम सकती है। अभी हालत यह है कि कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान में बच्चों की जन्मदर 0.97 प्रतिशत है तो जन्मदर 0.6 है। कोरिया में प्रजनन दर 0.72 प्रतिशत है। इस तरह देखें तो जन्म

